मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | मई, 2019 | अंक 5 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

किसानों को एक सपना बेचाा गया था कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन अब किसानों को यह महसूस करने के लिए मजबूत कारण हैं कि उन्हें धोखा दिया गया था। राजनैतिक दलों के घोषणापत्र बताते हैं कि राजनेता चाहते हैं कि हम मानें कि वे क्या करना चाहते हैं। चुनाव के बाद, विजेताओं को या तो चयनात्मक भूलने की बीमारी (प्रत्येक बैंक खाते में 15 लाख रुपये), पुनः व्याख्या के वादे (सी 2 + 50% पर एमएसपी), सफलताओं के रूप में विफलताओं (फसल बीमा) को जारी रखने या प्रस्तावित करने के लिए नीतिगत फाईन–प्रिंट के लिए जारी रखें घोषणापत्र उदारता (कृषि ऋण माफी) के लाभार्थी। क्रियाओं को भी प्रकट अर्थव्यवस्थाओं के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था (डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी) को बर्बाद कर देती है और परिणामस्वरूप बेरोजगारी प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

नौकरियों का सृजन करने में असमर्थ (5 वर्षों में 100 मिलियन नौकरियों का वादा किया था) या 'मेक इन इंडिया' की पहल को छोड़ दें, बीजेपी ने खोए हुए कारणों के साथ जो सबसे बुद्धि मानी की थी, वह यह थी। मैंने भोलेपन से यह अनुमान लगाया था कि '2022 तक किसानों का आय दोगुनी' का नारा बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यह वापस आ गया है।

पृथ्वी जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक पूंजी को कम करने की ग्रहों की सीमाओं के टिपिंग बिंदु को पार करने के कगार पर है। हर चीज की एक कीमत होती है, जिसे हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, जिसमें वह भी शामिल नहीं है, जिसका प्रयास भी नहीं किया गया था। हमारे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, जिसके परिणामस्वरूप भूजल तालिका गिर रही है, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण बिगड़ रहा है। हालांकि यह आज के खाद्य अधिशेष और कम जिंस कीमतों को उत्पन्न करता है, यह कृषि संकट को भी बढ़ावा देता है।

विडंबना यह है कि इससे किसानों की मांगों के प्रति सार्वजनिक रूप से अपमान और नीतिगत उदासीनता पैदा हो रही है। हम जिस राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं, उसके तत्काल प्रभाव से राजनीतिक दल भी थाह नहीं पा रहे हैं।

नकदी में किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी (उर्वरक और बिजली) स्थानांतरित करना समय की आवश्यकता है। यह निर्वाह के लिए नकदी हस्तांतरित करने के प्रयासों से पहले होना चाहिए। राजनेताओं ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित बड़े नकद हस्तांतरण को मौजूदा सब्सिडी को हटाकर वित्त पोषित नही किया जाएगा। मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता, क्या यह इच्छादारी सोच या दृढ़ इच्छाशक्ति है।

नकद हस्तांतरण पर सलाह देने वाले विशेषज्ञों ने इसे सब्सिडी के 'युक्तिकरण' के रूप में तैयार किया है जो सब्सिडी को कम करने या हटाने का एक शैक्षणिक तरीका है। मेरा डर यह है कि आने वाला फंड कंच न केवल एक पड़ाव में पहुंच जाएगा, स्वांस्थ्य सेवा और शिक्षा की आवश्यक बुनियादी सेवाओं में सुधार होगा, जो स्वीकार्य स्तरों से काफी नीचे हैं, बल्कि उत्पादक सार्वजनिक निवेश के प्रवाह को भी प्रभावित करेगा। सिद्धांतकारों द्वारा प्रचारित, राजनेताओं द्वारा टिल्स्ट किया गया, नौकरशाहों द्वारा ठीक–ठाक फाईन–प्रिंट फाइंग पैन से आग में कूदने के बराबर है।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

@ajayvirjakhar

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

पद्मश्री पुरस्कार 2019 जीतने वाले किसान

श्रीमति राजकुमारी देवी

घर की दहलीज के पार खेत में कदम रख सरैया प्रखंड के आनंदपुर गांव की राजकुमारी देवी पहले 'साइकिल चाची' और फिर 'किसान चाची' बनीं। मुजफ्फरपुर की 'किसान चाची' को बिहार सरकार ने वर्ष 2007 में 'किसान श्री' से सम्मानित किया था। अहमदाबाद में राजकुमारी देवी की लगन की तारिफ श्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी।

राजकुमारी देवी समाज के लिए आदर्श बन गई हैं। घर से बाहर कदम रखने पर जिस समाज ने उन्हें ठुकराया था आज वही समाज व परिवार उनके कारण अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

जिला मुख्यालय से करीब 30 कि.मी. दूर सरैया प्रखंड का आनंदपुर गांव है। यहां के एक घर का कोना–कोना कृषि उत्पादों से अटा पड़ा है। आम, अदरख, ओल के अचार तो आंवला व

बेल के मुरब्बे की खुशबू आपको बरबस यहां खींच लेगी। छोटी सी किसानी से भी परिवार कैसे खुशहाल हो सकता है, यह घर इसकी मिसाल है।

इसके पीछे है राजकुमारी देवी का त्याग। शादी के नौ वर्ष तक संतान नहीं होना और पति की बेरोजगारी के कारण घर की दहलीज से बाहर कदम रखने वाली एक बहू को समाज व परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया था। मगर, उस बहू की दृढ़ इच्छाशक्ति को उसी समाज ने आज किसान चाची का न केवल नाम दिया, बल्कि सम्मान भी।

खेत में रखा कदम

राजकुमारी कहती हैं, करीब 15 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। शिक्षक पिता ने प्यार से पाला था, मगर ससुराल में स्थिति उलट थी। जब तक कुछ समझते परिवार ने अलग कर दिया। सिर्फ जमीन से परिवार चलाना संभव नहीं था।

शादी के कई वर्ष तक संतान नहीं होने के कारण पहले से तिरस्कार झेल रही थी। उस पर से खेती शुरू की। परिवार के साथ अब समाज ने बहिष्कृत कर दिया। मगर, राजकुमारी के कदम नहीं रूके। उन्होंने खेती के साथ छोटे–मोटे कृषि उत्पाद बनाने शुरू किए। साइकिल उठाई और गला–ठेला व घर–घर जाकर इसकी बिक्री शुरू की। भूखे रहने पर नहीं पूछने वाला समाज दो रोटी कमाने के इस तरीके पर और सख्त हो गया। यहां तक कि अबकी बार पति भी नाराज। पति अवधेश कुमार चौधरी कहते हैं, साइकिल से सामान बेचना अच्छा नहीं लगा।

बढ़ता गया कारवां

रूढ़िवादी समाज जैसे–जैसे सख्त हो रहा था राजकुमारी का संकल्प उतना ही मजबूत हो रहा था। कुछ बेहतर करने के लिए खाद्य–प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लिया। पूसा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़कर आधुनिक तरीके से खेती के गुर सीखे। अचार व मुरब्बे के काम को बढ़ाया। आसपास की महिलाएं व युवतियों को प्रशिक्षण दिलाकर इस काम में लगाया। स्थिति बदलने लगी। दो बेटी व एक बेटे के रूप मे तीन संतानों ने भी जन्म लिया।

महज डेढ़ सौ रूपये से शुरू किया गया कारोबार बढ़ता गया। इसके साथ ही नाम भी। बिहार सरकार ने वर्ष 2007 में किसानश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वालीं एकमात्र महिला थीं। इस सम्मान के बाद ही 'साइकिल चाची' का नाम 'किसान चाची' हो गया।

प्रशंसकों में नरेंद्र मोदी, नीतिश व बिग बी भी

अचार व मुरब्बे के तरह किसान चाची का नाम भी फैलने लगा। अहमदाबाद में उनकी इस लगन की तारीफ नरेंद्र मोदी ने भी की। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार खुद इनकी खेती व छोटे से कारोबार को देखने इनके घर आए। एक चैनल पर आयोजित कार्यक्रम 'आज की रात है जिंदगी' में अमिताभ बच्चन के साथ किसान चाची के कार्यक्रम का प्रसारण हो

चुका है। कार्यक्रम के दौरान बिग बी उनसे खासे प्रभावित हुए। .....अमिताभ के फोन को समझ रहीं थीं मजाक। तब मैंने दिल्ली के प्रगति मैदान में अपना स्टॉल लगाया था। मोबाइल पर एक फोन आया। पति ने उठाया तो आवाज आई 'मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ'। लगा कोई मजाक कर रहा है। पति ने फोन काट दिया। कई बार इसी आवाज से फोन आया। आजिज आकर वहां मौजूद एक अधिकारी को मोबाइल दिया।

उन्होंने बात समझी। बताया गया कि एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अमिताभ बच्चन बात करना चाह रहे हैं बात हुई तो मुंबई बुलाया गया। बस क्या था, पकड़ ली मुंबई की फ्लाइट। कार्यक्रम के बाद पांच लाख रूपये, आटा चक्की व साडियां किसान चाची को भेजे गए। राशि से कारोबार में काफी मदद मिली।

महिलाओं को नहीं देखें हीन भावना से

महिलाओं के प्रति समाज के दोहरे मापदंड आज भी किसान चाची को खलता है। कहती हैं, वे किसी से कम नहीं। बस साथ लेकर चलिए। फिर देखिए।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

श्रीमति कमला पुजारी

ओडिशा के कोरापुट जिलें में एक आदिवासी बहल गांव में एक गरीब परिवार में जन्मीं, कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च को पद्मश्री से सम्मानित किया।

यह पहली बार नहीं है जब कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए पहचाना गया है। इससे पहले, उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ महिला किसान' सहित कई पुरस्कार मिले थे। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं इसके लिए ओडिशा के जेयपोर में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सिखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की।

अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद, कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर–घर जाकर आस–पास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके परिणामों के परिणामस्वरूप पटपूत गांव और नबरंगपुर जिले के पड़ोसी गाँवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। 2018 में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा राज्य बोर्ड ने कमला को इसके सदस्यों में से एक के रूप में जोड़ा।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

भारत के खाद्य प्रसंसाधन आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना

पिछले वर्ष मई में कई समाचार पत्रों में टमाटर, आम और लहसून के मूल्य कम हुऐ और किसानों को इनकी बिक्री में नुकसान हुआ। कुछ मामलों में किसानों ने अपने उत्पाद को सड़कों पर फेंक दिया। पर्याप्त भंडारण सुविधाऐं न होने के कारण किसानों को इन जल्दी सड़ने वाली सब्जियों को हानि पर ही बेचना पड़ा क्योंकि उनके पास परिवहन का किराया देने के लिऐ भी पैसे नहीं थे।

खाद्य–प्रसंस्करण से ऐसी वस्तुओं को भंडारित करके बाद में बेचा जा सकता है और इन्हीं फल और सब्जियों को जूस, जैम और अचार बनाकर भी बेचा जा सकता है। इसी उद्योग में इन्हें पकाने के लिऐ और संरक्षित करने के लिऐ वैक्सिंग, पैकेजिंग और लेबल करने जैसे कार्य भी शामिल हैं।

वर्ष 2001–02 और 2016–17 के बीच अनाज का उत्पादन 1.7 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा जबकि बागवानी फसलों का उत्पादन 4.8 प्रतिशत बढ़ा। उत्पादन ज्यादा होने के कारण और अच्छी खरीद, भंडारण और प्रसंसाधन जैसी शीत–भंडारण और खाद्य–प्रसंसाधन युनिट की कमी से अत्यधिक क्षति पहुंची।

वर्ष 2015 में फलों और सब्जियों की फसलों की हानि 7–16 प्रतिशत और अनाज की लगभग 5 प्रतिशत हानि हुई। अनाज की तुलना में फल और सब्जियां अधिक हानि देने वाली होती हैं, क्योंकि इन्हें भंडारित नहीं किया जा सकता।

अनुमान है कि वर्ष 2015 में मुख्य कृषि फसलों के उत्पादों की कुल फसल और फसल के बाद होने वाली वार्षिक हानि लगभग रू. 92,651/– करोड़ थी। कृषि संबंधी स्थाई समिति का कहना है कि पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध कराकर इस हानि से बचा जा सकता है।

किसानों के खेतों के पास अथवा कहीं नजदीक प्रसंसाधन की सुविधाऐं न होने से उन्हें अपनी फसलों को हानि पर बेचना पडता है, चाहे बाजार में वे महंगे दामों में बिके। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाऐं जैसे कोल्ड–चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर और मार्किट लिंकेज को मजबूत किया जाऐ।

कोल्ड–चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंसाधन युनिट, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटिड वैन शामिल हैं। शीत भंडार को अन्य ढुलाई जैसी सुविधाऐं उपलब्ध कराने से दूर–दूर के क्षेत्र में इनकी बिक्री करने पर किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है।

भारत में बढ़ी संख्या में कोल्ड–स्टोरेज हैं किंतु इससे संबंधित अन्य सहायक मूल सुविधाऐं और ढांचा उपलब्ध नहीं है। भारत में 32 मिलियन टन की शीत भंडार क्षमता उपलब्ध है, लेकिन वहां से रेफ्रिजरेटिड वैन जैसे परिवहन की उपलब्धता 15 प्रतिशत है।

फसल आने के बाद होने वाली हानि को कम करने के लिऐ स्थाई समिति (2017) ने सिफारिश की है कि देश के राज्यों में जिला और ब्लॉक स्तर पर एक समेकित कोल्ड–चेन ढांचे का नेटवर्क तैयार किया जाऐ। उसकी यह भी सिफारिश है कि किसानों को फसलों का मूल्य बढ़ाने के लिऐ उत्पाद की छटांई, ग्रेडिंग और प्रीकूलिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाऐ ताकि वे अपनी फसलों से अधिक आय प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2008 और 2017 के बीच 238 कोल्ड–चेन की परियोजनाऐं स्वीकार की गई, जिनके लिऐ रू. 1,775/– करोड़ भी स्वीकार किऐ गऐ। कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 114 (48 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं और शेष 124 पर कार्य चल रहा है।

वर्तमान में मुख्य अनाज और कुछ मात्रा में चाय, आलू और प्याज का लदान रेलवे द्वारा किया जाता है। समिति ने सिफारिश की है कि इन ताजे फल सब्जियों को सीधा निर्यात केन्द्रों तक पहुंचाने के लिऐ रेलवे अपने ढलान वाहनों के ढांचे को उन्नत बनाऐ।

मार्च 2018 तक अनुमोदित 42 परियोजनाओं में से 10 में काम आरंभ हो चुका है। कृषि संबंधी स्थाई समिति ने ऐसी परियोजनाओं के लागू होने में विलंब के कई कारण बताऐ। इनमें प्रमुख हैं – 1. ऐसी परियोजना के लिऐ बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई, 2. सडक, बिजली और जल की परियोजना स्थल पर व्यवस्था करने के लिऐ राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों की स्वीकृति मिलने में देरी, 3. मेगा पॉर्कों में आहार प्रसंसाधन एक्क लगाने के लिऐ विशेष प्रोत्साहन देने की कमी और, 4. को–प्रोमोटर्स द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अपने अंश को देने पर असहमत होना।

यदि इन सुझावों को सही प्रकार से लागू किया जाऐ तो देश में खाद्य प्रसंसाधन ढांचागत सुविधाओं में काफी सुधार किया जा सकता है। बढी मात्रा में खाद्य प्रसंसाधन ढांचागत सुविधाऐं उपलब्ध होने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर और उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा और वे अपनी फसलों और अन्य उत्पादों को हानि पर बेचने से भी बचेंगे।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

एक समृद्ध भारत की रीढ़ के रूप में किसान

भारत का लक्ष्य एक कृषि उन्मुख देश होना चाहिए था। और चूंकि ऐसा नहीं है, एक नई कृषि नीति को लागू किए जाने की जरूरत है ताकि किसानों को सिंचाई सुविधाएं, बाजार, बुनियादी संरचना इत्यादि सुलभ हो सके।

"मैं तो यह कहूँगा कि यदि गांव तबाह होते हैं, तो भारत भी तबाह हो जाएगा। भारत देश भारत नहीं रह जाएगा। दुनिया में इसके स्वयं का मिशन कहीं खो जाएगा। गांवों का पुनर्जीवन तभी होगा जब गांवों का और दोहन नहीं हो।" ये कथन थे महात्मा के, जो यह मानते थे कि भारत तब तक विकासित या समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि हमारे ध्यान का केन्द्र बिन्दु गांवों

के विकासित करने के महत्व से हटता रहेगा। आज, हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े टकराव का सामना कर रहे हैं क्योंकि राजनैतिक पार्टिया एक दूसरे पर किसान–विरोधी होने का लांछन लगा रही हैं। हालांकि, हर आने वाली सरकारें किसानों के हितो के बारे में लापरवाह रही हैं। वे एक ऐसे समाज के निर्माण में असफल रही हैं जिसकी जड़े ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती हों तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए हो।

वास्तव में, भारत में विकास की शैली पर कभी भी कोई बौद्धिक परिचर्चा हुई ही नहीं है। हमें हमारे समाज की नैतिकता, हमारे समग्र संसाधन के बंदोबस्ती और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को बनाए रखना चाहिए, जो कि भारत की आबादी के आकार व फैलाव की विशेषता है। सही रूपों में, स्वतंत्रता के शुरूआती वर्षों में, हमने फैबियन समाजवाद के ऐसे स्वरूप के ईर्द–गिर्द घूमते रहे, जो कि भारी उद्योगों पर केन्द्रीयकृत विकास पर जोर देने के साथ–साथ सोवियत मॉडल की ओर आकर्षित रहा। हाल के वर्षों में, हम उत्तरी अमेरिका के उपभोक्तावाद और पूंजीवाद मॉडल पर संचालित शैली की ओर अग्रसर हुए हैं।

भारत का कृषि उत्पादन क्षेत्र चीन से कहीं अधिक बड़ा है। फिर भी, खाद्य एवं कृषि संगठनों की सांख्यिकी के आधार पर, वर्ष 2010 में, चीन ने 483.3 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया और भारत ने केवल 250.8 मिट्रिक टन का। प्रति हेक्टेयर पैदावार के संदर्भ में, वर्ष 2010 में चीन ने 55 एचजी/हेक्टेयर दर्ज किया और भारत ने केवल 27 एचजी/हेक्टेयर का। यहां तक कि इंडोनेशिया और ब्राजील की पैदावार अधिक थी तथा संयुक्त राज्य, फ्रांस और जर्मनी ने इस क्षेत्र में 70 एचजी/हेक्टेयर पैदावार की।

अतीत में कई दशकों की विफलताओं में से एक रहा है पूरे देश में कृषि अनुसंधान तथा विस्तार प्रणाली की प्रभाविता में कमी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक, बी.पी. पाल, एक बौद्धिक नेता और दूरदर्शी वैज्ञानिक, जिन्होंने देश की हरित क्रांति की परिकल्पना कर इसकी शुरूआत की थी, ने एक मिशनरी उत्साह से प्रेरित होकर देशव्यापी बहुआयामी संगठन की स्थापना की।

एक ओर जहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन वर्षों में व्यापक तौर पर विस्तार किया है, यह अपने बहुआयामी, दूरदर्शी संसाधन की प्रभावित को कहीं खो चुका है। अब यह नौकरशाही के जाल में फंस चुका है और इसमें अब स्वायत्तता का अभाव है एक ऐसा रोग जो भारत के कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में लिए हुए है। दोनों, केन्द्र और राज्य की सरकारें अक्सर यह मानती हैं कि ऋण देने और आसानी से वित्त मुहैया कराने मात्र की आवश्यकता है जिससे कि कृषि में उच्चतम उत्पादकता और प्रगति को हासिल किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र कई विविध कारकों की मजबूती पर विकसित होते हैं, जिसमें शामिल हैं समुचित सिंचाई व्यवस्था, बाजारों का सुलभ होना, तर्कसंगत मूल्य समर्थन योजनाएं, कोल्ड चेन

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20

प्रकाशन की तिथि : 1 मई, 2019
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, मई 2019

की मौजूदगी (खासकर फलों और सब्जियों के लिए), और लगाातार नवाचार जिससे कि "हर बूंद अधिक फसल' तथा सभी संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

जल की उपलब्धता के मामले में, हमें जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के निष्कर्षों को ध्यान में रखना होगा, जो स्पष्ट तौर पर आवृत्ति और भारी वर्षा सहित चरम घटनाओं की तीव्रता में वृद्धि को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे और अनुकूलन उपायों की तत्काल आवश्यकता है, जिसके द्वारा किसानों की भलाई के साथ–साथ उनकी आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि कृषि अनुसंधान प्रणाली को फसलों की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने की जरूरत है ताकि वर्षा के अभाव में किसानों के पास विकल्प मौजूद हों।

जल का उन्नत प्रबंधन भी पूरे देश में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को हल्का करेगा, जैसा कि बुनियादी ढांचों का सृजन भारी वर्षा के मामले में खड़ी फसल को बचाने में सहायक होगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली भी किसानों के लिए काफी मददगार होगी।

भोजन और खाद्य उत्पादों के मूल्य वार्षिक तौर पर वैश्विक बाजार में उतरते–चढ़ते रहेंगे, लेकिन कृभाक समुदाय के लिए समुचित नीतियों और मूल्य समर्थन कार्यक्रमों के साथ व्यापक तौर पर फैली फसल बीमा योजनाएं आय में सामयिक गिरावट की गतियों के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला कर सकती हैं।

पूरे देश में समग्र तौर पर आर्थिक गतिशीलता के लिए कृषि आधिक्य एक प्रमुख शक्ति हो सकती है। बद्तर खाद्य आपूर्ति की ओर तेजी से बढ़ती दुनिया में, कृभाक समुदाय के लाभ के लिए बढ़ते राजस्व को पैदा करने के अलावा, भारत में कृषि आधिक्य का उपयोग गरीबों तथा खाद्य की कमी झेल रहे राष्ट्रों की मदद के लिए किया जा सकता है।

पूरी तरह एक नई और दूरदर्शी नीति को लागू किया जाना चाहिए जिससे कि भारत के कृषि आधिक्य राष्ट्र बनने को सुनिश्चित किया जा सके, जहां कि ग्रामीण विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।